कार्रवाई का समय

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

02 नवम्बर, 2021

G-20 बैठक वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में आई है।

दो साल में अपनी पहली व्यक्तिगत (आभासी नहीं) मीटिंग में, G-20 के नेताओं ने आज वैश्विक समुदाय के सामने सबसे बड़े मुद्दों के साथ फिर से जुड़ने में संकोच नहीं किया, जिसमें COVID-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन, एक प्रमुख कर समझौता, वैश्विक आर्थिक विकास और स्थिरता के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए भी इसमें कई कदम शामिल हैं।

महामारी को कम करने के समन्वित प्रयासों पर, टीके के उत्पादन और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें डब्ल्यूएचओ के 2021 तक 40% या अधिक वैश्विक आबादी को कोविड -19 के खिलाफ और 2022 के मध्य तक कम से कम 70% टीकाकरण के लक्ष्य के समर्थन का आश्वासन दिया गया।

G-20 नेताओं की इस प्रतिबद्धता में निहित धारणा यह है कि विकासशील देशों में टीकों की आपूर्ति को बढ़ावा देने की पहल सफल होगी, और सहयोग से दुनिया को आपूर्ति और वित्तपोषण बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन पर, समूह के नेताओं ने विकासशील देशों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुकूलन, शमन और हरित प्रौद्योगिकियों के लिए प्रति वर्ष $ 100 बिलियन प्रदान करने के लिए अपने राष्ट्रों की सिफारिश की।

हालांकि, इस क्षेत्र में विकासशील और विकसित देशों में विचारों का विचलन अभी भी मौजूद है। इस शिखर सम्मेलन और ग्लासगो में आयोजित हो रहे 2021 के जलवायु सम्मेलन से पहले भारत ने शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा करने के आह्वान को खारिज कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस संबंध में एक जीत हासिल की है क्योंकि शिखर सम्मेलन के बाद की विज्ञप्ति G-20 को ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध है साथ ही टिकाऊ और जिम्मेदार खपत और उत्पादन को "महत्वपूर्ण प्रवर्तक" के रूप में पहचानती है।

लकवाग्रस्त लॉकडाउन के बाद चल रहे नाजुक पोस्ट-कोविड आर्थिक सुधार के संबंध में विश्व समुदाय अस्थिर स्थिति में है। अप्रत्याशित रूप से, बढ़ती मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला की खतरनाक बाधाओं को देखते हुए, G-20 नेताओं ने यह पुष्टि करने के लिए जल्दी किया कि राष्ट्रीय प्रोत्साहन नीतियों को समय से पहले नहीं हटाया जाएगा।

फिर भी, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और राजकोषीय स्थिरता के बीच की कड़ी पर चलना एक चुनौती बनी रहेगी। शायद वैश्विक वित्त में संभावित दुर्बलता से बचने के लिए, G-20 नेतृत्व "अधिक स्थिर और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली" बनाने के लिए न्यूनतम 15% कर के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस के अंतर्गत लाने पर सहमत हुआ।

यह सिलिकॉन वैली के तकनीकी दिग्गजों को प्रभावित करेगा, क्योंकि इस पहल से ऐसी कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत कम कर वाले क्षेत्राधिकार में खुद को स्थापित करने से लाभ प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।

ओईसीडी के नेतृत्व वाले इस सुधार को 136 देशों का समर्थन प्राप्त है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 90% से अधिक है, और इसके 2023 या उसके बाद लागू होने की संभावना है।

यू.एस. जैसे राष्ट्र इस बात पर विभाजित हैं कि क्या इस प्रस्ताव को घरेलू स्तर पर अनुमोदित किया जाए, और जब तक कि चर्चा करने वालों के बीच एकमत न हो, पहल को कार्यान्वयन में देरी का सामना करना पड़ सकता है। G-20 बैठक वैश्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण में आई है। यदि इसका परिणाम प्रमुख देशों में समय पर, प्रभावी, समन्वित कार्रवाई में होता है, तो वसूली की आशा बनी रहेगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. जी-20 की बैठक निम्नलिखित में किस देश में आयोजित की गई?

(a) भारत

(b) ब्रिटेन

(c) इटली

(d) फ्रांस

Expected Question (Prelims Exams)

Q. In which of the following countries was the G-20 meeting held?

(a) India

(b) Britain

(c) Italy

(d) France

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. जी-20 देशों की बैठक में हुए निर्णय किस प्रकार से वर्तमान पोस्ट-कोविड 19 विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे? चर्चा करें। (250 शब्द)

Q. How will the decisions taken in the meeting of G-20 countries prove beneficial for the current post-covid 19 world? Discuss. (250 Words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।